(ii) The surrenderees are paid cash incentives for surrendered weapons at fixed scales. They are paid a stipend of Rs. 1500/-per month (Rs. 500/- for diet and Rs. 1000/- cash) during their stay in the Rehabilitation Centre.

(iii) As far as possible, and depending on their qualifications, efforts are made to provide them jobs in Defence Forces, CPMFs, Police, Public undertakings or even in private sector, subject to their fulfilling laid down qualifications.

(iv) At the Rehabilitation Centre, they are given vocational training in various trades like fitter, electrician, welder, stenographer, cutting and tailoring. After training, efforts are made to rehabilitate them by providing either suitable jobs or self-employment under various Central and State Schemes as per their choice and aptitude.

(v) The Policy, however, does not extend to surrenderees who are involved in cases of murder, rape, abduction and other such heinous crimes who will be subject to the due process of law and surrender would not lead to amnesty.

अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किराये के रूप में सरकार को देय राशियों की माफी

*63. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: चौधरी हरमोहन सिंह:**

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और आई०सी०सी०आर० के अध्यक्ष द्वारा किराये के रूप में सरकार को देय लाखों रुपये माफ कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने अन्य भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व संसद-सदस्य अभी भी सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(घ) क्या इसी तरह से उक्त बकाया राशि भी माफ करने का कोई प्रस्ताव है?

शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन): (क) और (ख) विभिन्न श्रेणी के अपात्र व्यक्तियों तथा संगठनों को सरकारी आवास आवंटित करने तथा उनसे लिए जाने वाले किराये के प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त सक्षम प्राधिकारी भूतपूर्व मंत्रियों तथा अन्यों के दखल वाले सरकारी आवास को विनियमित करने और लिए जाने वाले किराये का निर्धारण करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार और निर्णय करते रहे हैं। आई०सी०सी०आर० के अध्यक्ष के मामले पर भी सक्षम प्राधिकारी ने इन अधिकारों के तहत् विचार करके निर्णय लिया था।

(ग) उन भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व सांसदों की सूची, जो अभी भी साधारण पूल आवास में रह रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक की ओर बकाया किराये की राशि विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उन भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व सांसदों की सूची जो अभी भी सरकारी आवास में रहे हैं तथा 31.10.1995 तक उनमें से प्रत्येक की ओर बकाया किराया राशि

क्र०सं०	नाम	आवास	बकाया राशि (रुपये)	टिप्पणी (किस अवधि का है)
	सर्वश्री			
1.	शरद पवार	5-जनपथ	1,13,054	सितम्बर-अक्तूबर, 95
2.	पं० रवि शंकर	95, लोदी इस्टेट	1,159	-वही-
3.	बी०एन० पाण्डेय	1, लोदी इस्टेट	8,231	जनवरी-अक्टूबर, 95
4.	मोहम्मद युनूस	1, तुगलक रोड	8,135	जून-अक्टूबर, 95
5.	एम० पदमानाभन	7, रायसिना रोड	4,87,541	जून-94—अक्टूबर, 95
6.	वी०पी० सिंह	1, तीन मूर्ति मार्ग	29,191	अप्रैल, 94 से अक्टूबर, 95 तक
7.	देवी लाल	16, तुगलक रोड	8,10,561	सितम्बर-90 से अक्टूबर-95 तक
8.	एच०के०एल० भगत	34, पृथ्वीराज रोड	6,22,215	जनवरी, 92 से अक्तूबर, 95 तक
9.	श्रीमती अकबरजहां बेगम	9, सफदरजंग लेन	5,664	मई 95, से अक्तूबर, 95 तक
10.	स्व० ओम मेहता	30, पृथ्वीराज रोड	12,817	मार्च, 95 से अक्तूबर, 95 तक
11.	सुबोध कान्त सहाय	सी 1/2, लोधी गार्डन	1,67,842	कोई नया बकाया नहीं दिसम्बर, 89 से अगस्त 91 तक की पुरानी बकाया राशि
12.	एन०डी० तिवारी	सी 1/9, तिलक मार्ग	3,027	1990-93 की अवधि की बकाया पुरानी राशि
13.	के०के० तिवारी	सी 1/24, पंडारा पार्क	10,650	जनवरी 90 (पुराना बकाया)
14.	एस० एस० बरनाला	सी 1/18, हुमायूं रोड,	1,91,313	
15.	भीष्म नारायण सिंह	सी 1/1, पंडारा पार्क	बकाया किराया राशि का अभी भी निर्धारण नहीं किया गया है।	

Use of low cost devices in rural areas

*64. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT
RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various low-cost devices, capable of being used in rural areas/homes, were recently demonstrated before the Consultative Committee on Science and Technology;

(b) if so, what are the details of these devices, their cost and the places where they are available; and

(c) what steps are being taken to popularise these items?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Yes, Sir. The following electronic devices were demonstrated by the Department of Electronics before the Parliamentary Consultative Committee for Scientific Department on 24th Auguts, 1995.

(i) Solar Lantern
(ii) Electronic Milk Tester